जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी
Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 16 संख्याः 186 प्रभात हिण्डौन सिटी, मंगलवार 7 मई, 2024 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले नाइट पैरट किसी अजूबे से कम नहीं हैं। जमीन पर विचरण करने वाले ये पक्षी उड़ने में भी सक्षम हैं। रात होने पर ही इनकी आवाज सुनाई देती है। करीब सौ वर्षों तक इन्हें विलुप्त माना जा रहा था। नाइट पैरट विश्व के सबसे रहस्यमय पक्षियों में एक हैं। सबसे पहले 1845 में रिकॉर्ड किए गए इन पक्षियों का अंतिम जीवित नमूना वैस्ट ऑस्ट्रेलिया में 1912 में संग्रहित किया गया था। उसके बाद ये गायब हो गए और 1912 से 1979 के बीच इनकी कोई पुष्टी नहीं हुई। फिर, सन् 2013 में वाइल्ड -लाइफ फोटोग्राफर जॉन युंग ने वैस्टर्न क्वीन्सलैंड में एक पैरट के कई फोटो लिए और कुछ सैकेण्ड का वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड किया। कई वर्षों की मेहनत व खोज के बाद अंततः जॉन को बहुत करीब से एक नाइट पैरट देखने को मिला। इस खोज को लेकर विश्वभर में इतनी उत्सुकता पैदा हो गई कि, सुरक्षा के मद्देनज़र इनकी वास्तविक लोकेशन को उजागर नहीं किया गया। अब पिछले कई वर्षों में परभक्षी बिल्लियों और जंगल में आग लगने की घटनाओं के कारण इनका प्राकृतिक आवास घट गया है और माना जाता है कि, अब ये गंभीर रुप से संकटग्रस्त हैं। हाल ही में गिब्सन डैज़र्ट के एक दूरस्थ क्षेत्र में किवाकरा रेंजर टीम ने इनकी आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं। यह पांचवी टीम है जिसने इन पक्षियों की आवाज़ें रिकॉर्ड करने में सफलता पाई है। इनकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग संरक्षण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं, जिससे इनका वर्तमान आवास क्षेत्र चिन्हित किया जा सकता है। एक बार जब वहां से पर्याप्त रिकॉर्डिंग प्राप्त हो जाएंगी तो नाइट पैरट का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक संरक्षण के लिए विशिष्ट स्थानों को चिन्हित कर पाएंगे। इस वर्ष किवाकरा रेंजर्स ने 5 अलग -अलग क्षेत्रों में साउण्ड रिकॉर्डिंग स्टेशन बनाए और रात में रिकॉर्ड की हुई आवाज़ें नाइट पैरट विशेषज्ञ डॉ. निक लीज़बर्ग को भेजीं। इस पक्षी की आवाज़ एकदम अलग है इसलिए इसे पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। डॉ. लीज़बर्ग ने कहा, जैसे ही हमें नक्शे पर नया बिंदू नज़र आता तो इसका अर्थ होता कि, नाइट पैरट की रेंज में कुछ और विस्तार हो गया है। यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है।

पूर्व मु.मंत्रियों को रायबरेली व अमेठी में पर्यवेक्षक बनाया गया है?

कांग्रेस को उम्मीद है कि, भूपेश बघेल व गहलोत अपनी अंटियां खोलेंगे इन दोनों प्रतिष्ठित सीटों के चुनाव को फाइनैंस करने के लिए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **अशोक गहलोत द्वारा अपने पुत्र वैभव के चुनाव के लिये सौ करोड़ रूपये का बजट रखने की चर्चाओं ने, गहलोत को दिलवाया अमेठी के पर्यवेक्षक का चार्ज।**
- **गहलोत, राहुल गांधी के चुनाव पर्चा भरने के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं थे, पर, प्रियंका गांधी के हैलिकॉप्टर पर किसी तरह चढ़ कर रायबरेली पहुँच ही गये। यह ''तथ्य'' उनकी प्रचार टीम के लिये पर्याप्त था, यह बात फैलाने के लिये कि, वे अभी भी गांधी परिवार के विश्वासपात्र व नज़दीकी हैं तथा अन्य जगहों पर उनकी क्या स्थिति है, उसका फर्क नहीं पड़ता।**
- **पर विचारणीय बात यह है कि, माना कि, कांग्रेस पार्टी में पैसों की भारी कमी है, पर, वी.आई.पी. सीटों के लिये पैसे का जुगाड़ क्यों किया गया है, बाकी साधारण सीटों को उम्मीदवारों के भाग्य पर क्यों छोड़ दिया गया है।**
- **उदाहरण के लिये, उड़ीसा में कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती का प्रकरण है। श्रीमती मोहंती ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली क्योंकि ए.आई.सी.सी. के प्रतिनिधि अजय कुमार ने उनसे साफ कह दिया कि, ए.आई.सी.सी. उनकी कुछ भी आर्थिक मदद नहीं कर सकती चुनाव में। श्रीमती मोहंती व उनके पति पत्रकार हैं, अतः चुनाव में अपने स्रोतों से खर्चा वहन करना उनकी बस की बात नहीं है, अतः उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा की।**

नई दिल्ली, 6 मई। अशोक गहलोत को अमेठी लोकसभा सीट तथा भूपेश बघेल को रायबरेली लोकसभा सीट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दोनों पूर्व मुख्य मंत्रियों से अपेक्षित है कि, वो आर्थिक संकट से जूझ रही कांग्रेस पार्टी को इन दोनों सीटों के लिए फाइनैंस मुहैया कराने में अपनी अंटियां खोलेंगे। फण्ड मुहैया करवाएंगे।

कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली, दोनों ही प्रतिष्ठित सीटें हैं, जहाँ गाँधी परिवार को स्थापित करना है कि, अभी भी ये दोनों सीटें उनके प्रभाव की सीटें हैं।

रोचक बात यह है कि, बाकी 15 सीटों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त क्यों नहीं किए गए हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कुल मिलाकर 17 सीटों से चुनाव लड़ रही है। सूत्रों का कहना है कि, अशोक गहलोत राहुल गाँधी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रियंका गाँधी के हैलिकॉप्टर में उनके साथ रायबरेली पहुँचे। कहा जा रहा है कि, इस अवसर पर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, वो जबरदस्ती वहाँ पहुँचे।

अब अशोक गहलोत के मित्रों ने यह कहना शुरु कर दिया है कि, गहलोत अभी भी गाँधी परिवार के नज़दीकी और विश्वास पात्र आदमी हैं और पार्टी में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'नीट पेपर लीक, 23 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखा'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को हुए नीट पेपर लीक की कड़ी आलोचना की और इसे 23 लाख बच्चों व उनके परिवार के साथ विश्वासघात बताया।

उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी

- **राहुल गांधी ने कहा कि, नीट पेपर लीक होने से 23 लाख विद्यार्थियों व उनके परिजनों के साथ धोखा हुआ है, इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो पेपर लीक पर कड़े कानून बनाए जाएगे।**

सरकार उन युवाओं के लिए अभिशाप बन गई है जो 12वीं कक्षा पास करने के बाद मैडिकल कॉलेज में प्रवेश का सपना देख रहे थे या सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे।

राहुल ने कहा, भाजपा सरकार गत दस साल से सरकार चला रही है और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैं आरक्षण के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगायी गयी 50 प्रतिशत की सीमा हटवा दूंगा'

राहुल गांधी ने रतलाम में आयोजित आमसभा में यह ऐलान किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **राहुल गांधी ने कहा, दलित, बैकवर्ड व ट्राइबल समुदाय को उतना आरक्षण दिया जायेगा, जितनी उसको आवश्यकता है**
- **गुजरात में बनास कांठा में आयोजित आम सभा में प्र.मंत्री मोदी ने राहुल के ऐलान पर पलटवार करते हुए कहा, ''कांग्रेस आरक्षण से छेड़-छाड़ इसलिए कर रही है, क्योंकि वह धर्म के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है।''**
- **मोदी ने इसी लय में आगे यह भी कहा कि, राहुल गांधी व उनके समर्थक घोषणा करें कि, वे संविधान में तब्दीली नहीं लायेंगे तथा धर्म क नाम पर आरक्षण नहीं देंगे।**

नई दिल्ली, 6 मई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बड़ी घोषणा करते हुए वादा किया कि उनकी पार्टी और गठबंधन जातिगत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा को हटाने तथा दलित, पिछड़ों और आदिवासी समुदायों का आरक्षण कोटा बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।

मध्यप्रदेश के रतलाम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि, "यह चुनाव संविधान बचाने की खातिर लड़ा जा रहा है। भाजपा और आर.एस.एस. संविधान को बदलना, समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और इण्डिया गठबंधन इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। राहुल ने संविधान की एक प्रति दिखाते हुए कहा कि "इस संविधान ने आपको जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार दिए हैं। नरेन्द्र मोदी इन अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं। वे पूरी सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने घोषणा की है कि यदि वे जीते तो संविधान को बदल देंगे। इसीलिए इन्होंने "400 सीटों" का नारा दिया, लेकिन 4 सौ तो छोड़िए, इन लोगों को 150 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। ये कहते हैं कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं आपको अभी से यह बताना चाहता हूँ कि हम आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों, पिछड़ों दलितों और आदिवासियों को जितने आरक्षण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन को चुनौती

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मई। चुनाव आयोग ने रायबरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गाँधी के नामांकन को लेकर दो शिकायतें स्वीकार की हैं, एक तो उनकी ब्रिटिश नागरिकता और हाल ही में मानहानि के केस में उन पर सिद्ध हुए

- **यह चुनौती किसी अनिरूद्ध प्रताप सिंह ने दो आधारों पर दी है, एक तो राहुल की ब्रिटिश नागरिकता, दूसरे हाल ही में मानहानि केस में उनका दोषी साबित होना।**

आरोप को लेकर।

शिकायतकर्ता अनिरूद्ध प्रताप सिंह ने एडवोकेट अशोक पाण्डे के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। पाण्डे ने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज करवाकर राहुल के नामांकन को रद्द करने की मांग की है।

एडवोकेट पाण्डे ने कहा, "पहले तो, राहुल गाँधी को दो साल की सजा मिली है, जिसके कारण वो चुनाव लड़ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जे.पी. नड्डा व मीडिया इंचार्ज अमित मालविया के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी कांग्रेस ने

कर्नाटक में दर्ज इस एफ.आई.आर. में भाजपा पर आरोप लगाया गया है कि, सोशल मीडिया पोस्ट के मार्फत कर्नाटक के विभिन्न समुदायों में वैमनस्य फैलाने की चेष्टा की गयी है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **सोशल पोस्ट में दिखाया गया है कि, कांग्रेस एक डब्बे में चार अण्डे रख रही है, जिन पर मुसलमान, एस.टी., एस.सी, ओ.बी.सी. लिखा है।**
- **जब इन अण्डों से चूज़े निकलते हैं, तब राहुल गांधी केवल उस चूज़े को आहार दे रहे हैं जिस पर मुस्लिम लिखा है तथा मुस्लिम चूज़ा अन्य चूज़ों को धक्के मार कर बाहर निकाल देता है।**

नई दिल्ली, 6 मई। एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, पार्टी के मीडिया प्रभारी अमित मालवीय और कर्नाटक के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाय. विजेन्द्र के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। आरोप है कि इस सोशल मीडिया पोस्ट में एस.सी. और एस.टी. समुदायों के वोटर्स को कथित रूप से भयभीत किया गया है।

कांग्रेस को एक धर्म विशेष का पक्ष लेने वाली पार्टी के रूप में चित्रित करने वाले एक एनीमेटेड वीडियो के जारी होने के बाद कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस ने इसकी शिकायत दर्ज करायी थी। सोशल मीडिया साइट "एक्स" भाजपा की कर्नाटक इकाई के ऑफीशियल हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियों में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कैरिकेचर के साथ एक घोंसला दिखाया गया है जिसमें चार अण्डे रखे हैं। एक अण्डे पर "मुसलमान" लिखा है, जबकि अन्य पर एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी। वीडियों में राहुल गांधी के अगले कैरिकेचर में उन्हें उसी चूज़े को "फण्ड्स" रूपी भोजन देते बताया गया है जो "मुस्लिम" अण्डे से निकला है।

वीडियो का कैप्शन है "सावधान, सावधान।" वीडियो में दिखाया गया है कि मुस्लिम अण्डे से निकला चूज़ा अन्य तीन अण्डों से निकले चूज़ों को धक्का देकर अलग करता है। उसके बाद हंसी की आवाज आती है।

कांग्रेस की शिकायत में कहा है कि वीडियो में पिछड़े समुदायों को अंडे के रूप में प्रदर्शित कर उनका अपमान किया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जेल का जवाब वोट से देंगे'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मई। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव प्रचार गीत "जेल का जवाब वोट से" को मंजूरी दे दी है, वो भी बिना किसी परिवर्तन के।

आप के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने

- **आप पार्टी के इस चुनाव प्रचार गीत को चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि, हम आयोग के निर्देशों के आगे नहीं झुके।**

सोमवार को बताया कि वे किस तरह से अपने पक्ष के लिए लड़े। उन्होंने कहा हम भाजपा के घटिया प्रयासों के आगे नहीं झुकेंगे।

पार्टी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब वोट से देंगे। पार्टी ने गुंडागर्दी के खिलाफ वोट देने की अपील भी की है।

चंद्रबाबू नायडू ने भी अफलातूनी प्रचार अभियान चलाया कि, सरकार परिवार की विवादित भूमि अधिग्रहित कर लेगी

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **चंद्रबाबू नायडू का तर्क है कि, सरकार ने सितम्बर 2022 को ''लैण्ड टाइटलिंग एक्ट'' पारित किया था, जिसके तहत, परिवारों की विरासत में मिली भूमि को, जिस पर उत्तराधिकारियों में विवाद है, सरकार अपने कब्जे में ले लेगी।**
- **सरकार इन ज़मीनों के रिकॉर्ड को ''डिजिटाइज़'' करने के लिये, प्रापर्टी के कागज़ात परिवार वालों से मांग रही है। पर, जनता द्वारा इस कागज़ातों को वापस लेने की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि, प्रापर्टी के ऑरिज़नल कागज़ात सरकार से प्राप्त करना अत्यन्त जटिल व लम्बा काम हो जाएगा, प्रापर्टी सरकार के कब्जे में ही चली जायेगी।**
- **चंद्रबाबू नायडू का प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में काफी असर डाल रहा है, तथा दहशत भी फैल गयी है।**

नई दिल्ली, 6 मई। भाजपा जिस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही है कि यह लोगों के मंगलसूत्र और पैसा छीन कर गरीब मुसलमानों को दे देगी। अब भाजपा की सहयोगी तेलुगूदेसम पार्टी ने जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाया है। लैंड टाइटलिंग एक्ट के जरिए यह सरकार आम जनता की ज़मीन-जायदाद हथिया लेगी। पता चला है कि इस मुद्दे पर चल रहे टैलिफोनिक अभियान के पीछे तेलुगूदेसम है। इनमें फोन करने वाला व्यक्ति बताता हैं कि लैंड टाइटलिंग एक्ट कुछ ही दिनों में लागू हो जाएगा और इसके बाद आपकी सारी ज़मीन सरकार हथिया लेगी। सत्तारूढ़ पार्टी वाय.एस.आर.सी.पी. ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है और साइबर सैल से एक्शन लेने को कहा है।

लेकिन गाँवों और कस्बों में लोगों में डर सा व्याप्त होने लगा है कि सरकार उन लोगों की ज़मीन व घर छीन लेगी जो उन्हें विरासत में मिली है। डर यह है कि कागज़ी कार्यवाही बेहद भ्रामक है कि कुछ लोग तो अपनी खानदानी जायदाद से वंचित हो जाएंगे। असल में सरकार लैंड रिकॉर्ड को "डिजाटलाइज़" करने जा रही है कानून के मार्फत, इसलिए लोगों से कागज़ात मांग रही है, पर इन कागज़ातों की वापसी की प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसलिए जनता के डर बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश में 13 मई को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा।

तेलुगूदेसम के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू सितम्बर 2022 में आंध्र विधानसभा पारित लैंड टाइटलिंग एक्ट को अपने प्रचार अभियान में लैंड ग्रैबिंग (कब्जा) एक्ट बता रहे हैं। जन सेना के प्रमुख पवन कल्याण भी फोन कॉल में कही गई बात दोहराते हुए कहते हैं कि जगन मोहन रेड्डी फिर से सत्ता में आए तो कानून का दुरुपयोग कर जनता की ज़मीन जायदाद छीन लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगूदेसम और जन सेना की सरकार सत्ता में आई तो वे इस कानून को खत्म कर देंगे।

आम जनता में डर है कि जिस ज़मीन के वे कानूनन हकदार है उसे सरकार किसी ना किसी बहाने से छीन लेगी। इस सबके पीछे तेलुगूदेसम है नायडू ने जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया कि रिकॉर्ड डिज़ीटल करने के नाम पर वे जनता की ज़मीन छीन लेंगे। तेलुगूदेसम ने बड़ी ही सफलता से लोगों के दिलों-दिमाग में यह डर घुसा दिया है। ऐसा डर है कि ऐसी ज़मीनें जिन पर कानूनी विवाद है या खानदानी झगड़ा है और जिनके पूरे कागज़ात नहीं हैं, उन ज़मीनों को सरकार ले लेगी। दूसरे जन्म, मृत्यु, स्थानीय निवास और अन्य दस्तावेज़ों, जो राजस्व विभाग जारी करता है, उन पर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का फोटो लगा है। विपक्ष लोगों से कह रहा है कि ये दस्तावेज़ संकेत हैं कि ज़मीन पूरी तरह से आपकी नहीं हैं कागज़ों पर जगन की तस्वीर की मौजूदगी को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। नायडू जन सभाओं में ये कागज़ दिखा कर जनता को और डरा रहे हैं।

नायडू जो कह रहे हैं वह तेलंगाना विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रचार से अलग नहीं है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि बी.आर.एस. सरकार के लैंड रिकॉर्ड पोर्टल में ज़मीनों की सुरक्षा संदिग्ध है।

लैंड टाइटलिंग विधेयक नीति आयोग के मॉडल ड्राफ्ट पेपर पर आधारित है। आयोग ने मकान व भूखंडों पर आम लोगों को ज़मीन का हक देने के लिए ऐसा कानून बनाने को कहा था, जिससे ज़मीन विवादों की संख्या में कमी आएगी और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स के अधिग्रहण के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनेगी।

वाय.एस.आर.सी.पी. को बहुत बाद में जाकर यह अहसास हुआ है कि लैण्ड टाइटलिंग एक्ट से जनमानस में नकारात्मक भावना निर्मित हो रही है, इसलिए जगन ने अब अपनी प्रत्येक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेठी और रायबरेली का प्रभार दो पूर्व मु.मंत्रियों को

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मई। सोमवार को कांग्रेस ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को वी.आई.पी. निर्वाचन क्षेत्र, रायबरेली व अमेठी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

ए.आई.सी.सी. महासचिव के.सी.

- **राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमेठी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल रायबरेली की चुनाव व्यवस्था संभालेंगे।**

वेणुगोपाल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेवारी दी गई है तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गाँधी की लोकसभा सीट रायबरेली का काम देखेंगे।